

प्रेषक,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवामें,

कुल सचिव,

पत्रांक: 1519 / दि0ज0स0वि0 / रा0छा0यो0 / 2024-25: लखनऊ :

दिनांक- 30 जुलाई, 2024

विषय:- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र-2024-25 के लिए प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक/टॉप-क्लास की भारत सरकार द्वारा निर्गत समय सारणी के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े दिव्यांग छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक सशक्तीकरण है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के माध्यम से दिव्यांगछात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है -

- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 09 और 10 के लिए)।
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)।
- उच्च श्रेणी शिक्षा (टॉप क्लास) छात्रवृत्ति (शिक्षा के उत्कृष्टता में अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)।
- राष्ट्रीय ओवर्ससीज छात्रवृत्ति (विदेश स्थित विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री पी0एच0डी0)।
- राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालय में एमफिल और पी0एच0डी0)।
- दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग (ग्रुप क और ख पदों के लिए मर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं)।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप-क्लास छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र-2024-25 हेतु समय-सारणी का विज्ञापन दिनांक-28.07.2024 को प्रकाशित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

समय-सारणी		
योजना	आरम्भ करने की तिथि	अंतिम तिथि
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.06.2024	31.08.2024
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति	30.06.2024 ✓	31.10.2024 ✓

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली की छात्रवृत्ति हेतु वेबसाइट www.scholarships.gov.in में उपलब्ध व्यवस्थानुसार समन्यार्तगत आप अपने विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्र/छात्राओं को योजनान्तर्गत से लाभान्वित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रणजीत सिंह)
संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2, उ0प्र0 शसान।
- वैयक्तिक सहायक, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।

(रणजीत सिंह)
संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक।

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक ०१ जुलाई, 2024

विषय: एकेडमिक वर्ष 2024-25 हेतु एस०सी० विद्यार्थियों के लिये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा एस०सी० व अन्य विद्यार्थियों के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री परवीन कुमार थिंद, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-K-11017/1/2022-SCD-V, दिनांक 08.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एकेडमिक वर्ष 2024-25 हेतु एस०सी० विद्यार्थियों के लिये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा एस०सी० व अन्य विद्यार्थियों के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश देते हुए सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में उक्त दिशा-निर्देशों का कियान्वयन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.07.2024 में की गयी अपेक्षा के क्रम में नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
/s/ (शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- श्री परवीन कुमार थिंद, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री गिरि), उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,
/ (एस०पी० मिश्र)
उप सचिव।

संख्या 23 आ० 66 / स० 3-2024

संख्या 8228 / VIP PSHED/202

No.K-11017/1/2022-SCD-V
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Social Justice & Empowerment
(SCD-V Section)

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 08th July 2024

To

Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Commissioner/
Additional Secretary/Incharges/
Social Welfare Department/SC/OBC Welfare Department
All States/UTs

Subject: Instructions regarding Implementation of Post Matric Scholarship Scheme (SC) Students and Pre-Matric Scholarship Scheme for SC Students & Others for AY 2024-25 - reg.

Respected Madam/Sir,

With reference to implementation of Post Matric Scholarship Scheme (SC) Students and Pre-Matric Scholarship Scheme for SCs & Others for AY 2024-25, it is informed that in addition to the Guidelines/instructions already issued to all States/UTs vide letter dated 5th October, 2023 (copy enclosed), following recommendations as approved by the competent authority need to be implemented by all States/UTs as listed below:

- For Pre and Post Matric Scholarship Schemes for SCs -Aadhaar based biometric authentication and eKYC is to be made mandatory from AY 2024-25.** All eligible beneficiaries, from AY 2024-25, need to have their Aadhaar based biometric authentication and eKYC to be completed during the application registration process. State/UT departments to make sure that the entire exercise is completed along with the registration and verification process.

All scholarship payments to be made using Aadhaar Payment Bridge (APB) System to ensure that payments are made only to the eligible beneficiary. DoSJE would also suggest the States/UTs to encourage APBS for disbursement of state share under the said scheme. No Account based payments are accepted for disbursement of central share under the scholarship schemes.

VS(S.6)

8.7.24

(आर०पी० चौधरी)
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

31821/KS/SC/2024/3

3

8.7.24
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन


10/7/2024

शश्वती कुमारी
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

3. Real time integration (REST API) of State Scheme portals with NPCI-State portals is mandatory to show the real time status of Aadhaar seeding for applicant at the time of registration. This would help in reducing the payment failure issues related to non Aadhaar seeding faced in previous years, while at the same time help applicants get their Aadhaar seeding status.
4. In case of non-seeding of Aadhaar with beneficiary's account, INO must ensure that the student's Aadhaar seeding is completed and form is finally submitted within 15 days of registration of application. Thereafter, the State Governments are requested to ensure that the state share of scholarship is disbursed within 30 days of INO verification. Reducing the turnaround time for scholarship disbursements is extremely important and the emphasis of the Ministry.
5. SNOs and DNOs are requested to arrange and organise Aadhaar seeding camps for the applicants in coordination with the banks at the institution level.
6. For States, it is required that there is mandatory integration with DigiLocker/API Setu/State Database for Digital/online Verification of eligibility certificates from AY 2024-25. For online verification of eligibility certificates/documents, States/UTs shall use DigiLocker/API Setu extensively for eligibility verification. It is recommended that integration among the different databases and other State departments with the State Scholarship Portals is completed by end of October this year. Basic eligibility documents specially the Caste Certificate, Income Certificate, Educational Certificates and Domicile Certificate required for applying for the scholarships should be fetched online.
7. Geo-tagging of institutes and Aadhaar based eKYC of all Institute Nodal Officers to be completed by October this year.
8. States must ensure that a facility/provision is in place through which beneficiaries are informed regularly about the status of their scholarship application. Once scholarship is released, the State Governments/UTs are required to notify the beneficiaries as well as the institutions through SMS, Email, or any other means.
9. Students must ensure that scholarship benefit received from the State and Central Government viz. Tuition Fee/Non Refundable Fee are paid to the institute within 7 days from the date of receiving of scholarship amount. It shall be the responsibility of the State Governments and concerned Institutions to mentor/counsel/guide the beneficiaries to pay/remit the said amount to the Institutions. States/UTs must have appropriate systems and policies in place to ensure this.

22/10/2023
DIRECTOR
INSTITUTIONS
HIGHER SECONDARY
EDUCATION
GOVT. OF INDIA
NEW DELHI

10. Institute must have valid and active AISHE or UDISE+ or NCVT or SCVT code in each record. Mandatory integration of State portals with UDISE+/AISHE & other similar databases for authentication of School/Colleges/Institutions from AY 2024-25.
11. Capturing the institution type – The Scholarship Portals should also capture the Institute type (Government/ Government Aided/Private) during the application verification process. The INO shall be responsible to capture, check and verify the type of Institution. It is imperative that the API be updated to include additional mandatory parameter that captures the type of institution from the State/UT.
12. Disbursement of State share: States shall have to clear all the pendency of AY 2022-23 & 2023-24, i.e., Disbursement of State Share, Aadhaar seeding failed cases and any other failure cases if any, at the earliest. States/UTs must also ensure data purification exercises are undertaken at regular intervals so that all redundant data, dummy data, duplicate data and incomplete data are removed from the system and scholarship portals.
13. Pending Utilization Certificates – States/UTs shall have to submit the pending Utilization Certificates for Administrative Funds issued in AY 2021-22 & 2022-23.
14. Aadhaar based Biometric eKYC for all INOs/HoIs/DNOs/SNO: From AY 2024-25, central share disbursement will take place only if, the concerned INOs/HoIs/DNOs/SNO has completed their Aadhaar based Biometric eKYC.
15. IEC & Capacity building: for all the activities related to IEC & Capacity building, States/UTs are suggested to arrange suitable & adequate mass awareness and outreach programmes which may be undertaken at regular and frequent intervals to ensure that the beneficiary students/institutions/department officials are aware of these requirements such that the larger goals of saturation and access to good education are achieved.
16. States/UTs are guided to create, maintain and regularly update the course master for the courses in Post Matric Scholarship Scheme.
17. As per the scheme guidelines, States/UTs need to ensure that Fee Rationalization/Fixation Committee is in place. Compulsory non-refundable fees including tuition fee, as fixed by the Fee Fixation/Rationalization Committee of the State Government shall be paid to the beneficiaries. It shall be ensured that Rates of academic allowance fixed by DoSJ&E, Govt. of India in the scheme guidelines shall be given to the beneficiaries.
18. States/UTs may decide/act for gainfully utilizing the administrative funds towards the suggestive activities that may be undertaken for smooth implementation of these two schemes:


[Faint, illegible text and stamp]

- i. Development and upgradation of IT Infrastructure;
- ii. Strengthening of existing capacity including of technical experts and manpower;
- iii. Capacity building and training of the existing staff and human resources;
- iv. Data integration, scheme implementation, analysis, monitoring and evaluation;
- v. IEC awareness, print, media & social media campaigns and outreach activities for saturation of these schemes; and
- vi. Physical verification including Social Audits of at least 10% Institutions/beneficiaries as per scheme guidelines.

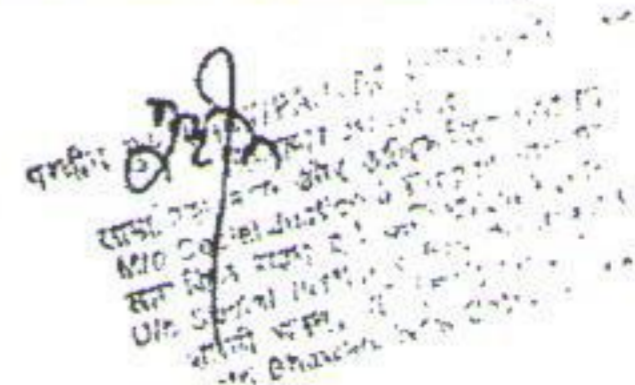
19. States/UTs are guided to take appropriate action on the below mentioned issues:

- vii. States/UTs need to capture active mobile number of INO mandatorily;
- viii. States/UTs need to capture date of birth of applicant as per Aadhaar details. In case of missing details, States/UTs need to ensure that Aadhaar details of beneficiaries are updated;
- ix. It is important to reiterate that all the Academic allowances for scholarships are on an annual basis, and not on month/semester basis;
- x. As per scheme guidelines, in case of minor students where the guardian/parent are providing their Aadhaar, biometric authentication of the guardian/parent shall only be taken (whose Aadhaar has been provided). Further, a single guardian/parent's Aadhaar shall be allowed for a maximum of 2 children (students).

20. For States/UTs on-boarded on NSP:

NSP has done complete overhaul of the system for AY 2024-25 including following major changes in AY 2024-25.

- i. UI/UX enhancements (in co-ordination with NIC UI/UX Division) to provide better user experience;
- ii. Introduced the concept of One Time Registration (OTR). FAQs are available in Students' section on National Scholarship Portal to know more about the OTR <link: <https://scholarships.gov.in/studentFAQs>>;
- iii. Students can apply for scholarship only after getting/generating the OTR number;
- iv. New Scholarship Application Form for Fresh and Renewal scholarship applications submission;

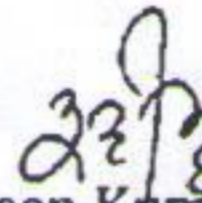

The stamp is circular and contains the following text: 'National Scholarship Portal', 'Ministry of Education', 'Government of India', and 'New Delhi'. There is a handwritten signature over the stamp.

- v. Introduction of Grievance Redressal for Application wherein, each student/INO/DNO/SNO can submit their grievances;
- vi. Option to disburse scholarship multiple times in an academic year; and
- vii. New on-boarding of institute through mandatory face-authentication of HoI and INO.

21. Aadhaar based Biometric eKYC for all INOs/Hols/DNOs/SNOs:

Attention is invited to the revised Instructions letter no. K-11017/1/2022-SCD-V dated 05th October 2023, wherein it was recommended that starting from 2023-24 States/UTs were required to complete the Aadhaar based Bio-metric eKYC for all INOs and HOIs of existing institutions followed by Aadhaar based Biometric eKYC for DNOs & SNOs. This step is aimed to bolster the authenticity and accuracy of identity verification processes.

Yours faithfully


 22/3.7.24
 (Parveen Kumar Thind)
 Director
 Email: pk.thind@ias.gov.in
 पारवीन कुमार थिंद / P.K. THIND
 Director
 M/o Social Justice & Empowerment
 सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग
 D/o Social Justice & Empowerment
 शासकीय भवन, अटल भवन
 Ashrafli Bazaar

Copy to:

1. Chief Secretary, All States/UTs as per list for kind information.
2. Shri Saurabh K Tiwari, Joint Secretary, DBT Mission, Cabinet Secretariat, New Delhi.
3. Shri Shashi Bhushan, HoG, NSP NIC, New Delhi.
4. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary/ Additional Secretary/Incharges of the Department of School Education, All States/UTs as per list for necessary cooperation and directions to all concerned for taking action on related aspects at the earliest.
5. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary/ Additional Secretary/Incharges of the Department of Higher Education, All States/UTs as per list for necessary cooperation and directions to all concerned for taking action on related aspects at the earliest.
6. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary/ Additional Secretary/Incharges of the Department of Medical Education, All States/UTs

as per list for necessary cooperation and directions to all concerned for taking action on related aspects at the earliest.

7. Commissioner/Director, Department of School Education, All States/UTs as per list; for necessary follow up and action.
8. Commissioner/Director, Department of Higher Education, All States/UTs as per list; for necessary follow up and action.
9. Commissioner/Director, Department of Medical Education, All States/UTs as per list; for necessary follow up and action.
10. HoG, National Scholarship Portal (NSP), NIC HQ.